उत्तराखण्ड शासन

विकित्सा स्वास्थ्य एवं विकित्सा शिक्षा अनुभाग-5

अधिसूचना

प्रकीर्ण

06 ਕਸ਼ੈਕ, 2020 ई0

संख्या 231/XXVIII(1)/20-22(सामान्य)/2015-राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विमाग (मेडिकल कॉलेज) के नर्सिंग सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की मर्टी तथा सेवा शर्तों को विनिविभित्त करने के लिए निम्नलिखित निवमावली बनाते हैं:--

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2020 भाग-1-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) यह नियमावली, उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियभावली, 2020 कहलायेगी।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति परिभाषाएं

- उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) (अराजपत्रित) नर्सिंग संवर्ग सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट है।
- जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकृत न हो, इस नियमावली में 🛨
- "नियुक्ति प्राधिकारी" से निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विमाग, उत्तराखण्ड अभिश्रेत है। (क)
- "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो "भारत का संविधान" के भाग-2 के (ख) अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है।
- "बोर्ड' से" उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड' अमिप्रेत है।
- "संविधान" से 'मारत का संविधान' अभिप्रेत है। (घ)
- "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है। (₹)
- ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है। (च)
- "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के (छ) अधीन स्थायी रूप से / मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत हैं।

"सेवा" का तात्पर्य उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) अराजपत्रित नर्सिंग (জ) सेवा से हैं।

- "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत हैं, जो तदर्थ **(닭**) नियुक्ति न हो और नियमानुसार भयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के परचात् की गयी हो तथा
- "भर्ती का वर्ष" से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की (33) अवधि अभिष्रेत है।

सेवा संवर्ग

- भाग 2-संवर्ग (1) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।
- सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (2) (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट-क में दी गयी है, परन्तु उपबन्ध यह है कि --
- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी यह को इस प्रकार प्रास्थिगत कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद स्जित कर सकते हैं जैसा के जिसा के जिसा

भाग 3-भती

- भर्ती का स्रोत सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की महीं निम्नलिखित सोतीं से की जायेगी <u>श्रेणी ग</u>
 - सिस्टर निर्मंग : मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे स्थायी स्टाफ नर्स में से, जिन्होंने मती के (ক) वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेया पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदीन्ति के माध्यम से मरा जाएगा
 - स्टाफ नर्स : शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा कुल पर्दों का 80 प्रतिशत महिला उपचारिका प्रतिशत पुरुष उपवारक होंगे। ध्यम वर्ष में महिला/पुरुष उपचारिकाओं / उपचारकों के कुल उपलब्ध रिक्त पदों में से 70 प्रतिशत पद अनसल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में डिप्लोमा धारक अम्यर्थियाँ तथा 30 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिग्री घारक अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग व आर्थिक 6. रूप से कमज़ोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अन्यर्थियों के लिए आखाण मती के समब प्रकृत सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4-अहता

- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अध्यर्थी -
 - (क) भारत का नागरिक हो ; या
 - तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से वसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए : या
 - भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु, उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके मक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) सं सम्बन्धित है प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आदश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अम्यर्थी के पास निम्न अर्हताएँ होनी 8. आवश्यक है-

> पद (ক) स्टाफ नसे

अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से इण्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में डिप्लोमा अथवा बी०एस०सी० (नर्सिंग) परीक्षा उत्तीर्ण की गयी हो।

अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड नर्स तथा धात्री परिषद् में रजिस्ट्रीकरण के योग्य जनरल नर्सिंग एवं निखवाइफरी का डिप्लोमा अथवा बीछएस०सी० नर्सिंग की डिग्री हो। बी०एस0सी० नर्सिंग के डिग्रीझारकों के पास राज्य

राष्ट्रीयता

आरक्षण

रौक्षणिक अर्हता

सरकार के विकित्सा संकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 01 वर्ष का नर्सिंग कार्य का अनुमद होना आवश्यक है।

क्षनिवार्य / वांछनीय अर्हता (ग) निर्सिंग काउन्सिल, उत्तराखण्ड में रिजस्ट्रीकृत हो। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सगूह 'ग' की गर्ती के लिए अनिवार्य/वाछनीय अईता नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित शर्तो/उपबन्धों के अनुसार होगी।

अधिमानी अर्हता

- 10. (क) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अविमान दिया जाएगा, जिसने—
 - (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो ; या
 - (2) नेशनल कैंडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

11.

जिस कलैण्डर वर्ष में रिक्तियों आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय या यथास्थिति, ऐसी रिक्तियों सेवायोजन कार्यालय की सूचित की जायें, उस वर्ष की 01 जुलाई को शासन द्वारा समय-समय पर यथा विहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए।

परन्तु, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियाँ के अभ्यर्थियाँ के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्रः

12. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 3. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसका एक से अधिक पति जीवित हो ;

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्त्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व, उससे—

(क) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिको खण्ड !! भाग !!! के अध्याय !!! में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत

करना अपेक्षित है :

प्रन्तु यह कि:
1) दिव्यांगत अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या--49)की धारा 33 के कम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत संदर्भित में दिव्यांग जनों को नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने से मना नहीं किया जायेगा।

2) पदोन्नित द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग 5-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अक्थारणा

15.

नियुक्ति प्राधिकारी / ययन बोर्ड वर्ष के दौरान गरी जाने वाली रिक्तियों की नियम के क्षीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछन्डे वर्ग तथा क्षीयिक कि से कमजोर वर्ग व अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की लेक्स कार्यारित करेगा और सैवायोजन कार्यालय / धयन बोर्ड को सूचित करेगा।

सीघी भर्ती की 18. प्रक्रिया

सैया में सीधी भर्ती पदों पर भर्ती उत्सराखण्ड (लोक सेया आयोग की परिधि के बाहर) समूह ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2008 (समय—समय पर यथासंशोधित) में निहित उपबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जायेगी।

पदोन्नति के 17. लिए भर्ती प्रक्रिया

- (1) पदोन्नित द्वारा भर्ती, उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नित समिति का गठन (लोक सेवा की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित उपबन्धों के अधीन गिहत चयन समिति द्वारा की जायेगी।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ कार्मिक विभाग के उत्तराखण्ड ज्यनीन्ति पात्रता सूची नियमावली 2003 के अनुसार होयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजिकाओं तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अमिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाये, विभागीय चयन समिति के समक्ष रखेगा।
- (3) विभागीय चयन समिति द्वारा उप नियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्योंकेंगें के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।
- (4) चयन समिति चयनित अम्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

भाग 6-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं स्थेष्ठता

नियुक्ति

18.

19.

- (1) उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम छस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 16, 17 अथवा 18 यथारिथति, के अधीन बनायी गयी सूचियाँ में हों. नियुक्ति करेगा।
- (2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नित दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी तब तक कि दोनों सीतो से स्थन न किया गया हो और नियम—18 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों।
- (3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उत्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम-18 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूथी में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूथियों का कोई अध्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अध्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियों एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेमी और जहाँ पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के विनियम 5 (क) के प्राविधान लागू होंगे।

परिवीका

- (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 92 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा;
 - (2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक-पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्देष्ट करते हुए जब सक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होते : परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

- (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि पश्चिता अवधि के दौराम किया नाम या परिविक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिविक्षा की बढ़ाई गयी अवधि के किसी परिविक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यव्य समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके नूल पद पर यदि कोई है. प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
- (4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- 5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अविधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरनार सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर मा
- ाकसा समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो। स्थायीकरण 20. (1) उपनियम—(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अविध या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अविध की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा; यदि—
 - (क) उसका कार्य और आवरण संतोषप्रद बताया जाय:

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय;

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) यदि 'उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002'' के अन्तर्गत स्थायीकरण आवश्यक न हो तो उक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन जारी किया यह आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 21. किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

माग 7-वेतन आदि

वेतनमान 22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुडोय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

> (2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय सेवा के विभिन्न पदों के वेतनमान वह होंगे जिनका उल्लेख परिशिष्ट (क) में दिया गया है ।

परिवीक्षा अवधि 23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी संतान सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम देतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि हो वर्ष की सेवा के परवात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी:

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिकेश अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गर्जी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी। (3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में है, सरकार के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जावेगा।

पक्ष समर्थन

- 24. किसी पद या सेवा पर लागू निवमावली के बडीन बपेक्षित सिफारिशों से मिन्न किसी सिफारिश पर चाहें लिखित हो वा मौखिक पर विधार नहीं किया जावेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अम्बर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।
- अन्य विषयों का 25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों वा विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लाम विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

भाग 8-अन्य उपबन्ध

सेवा की शतों में 26. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शतें विशिषानिकरण विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुवित किनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शतों के अधीन इस नियम की अपेकाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोखित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रिवायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यवियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेकित हो।

<u>परिशिष्ट-क</u> पदनाम, वेतनमान एवं पदों की संख्या

	·		
क 0 ₹10	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1. R	स्टर नसिंग	₹ 47,600—1,51,100 (लेवल-6)	160
	ॉफ नर्स	₹ 44,900—1,42,400 (लेवल-7)	1091

आज्ञा से.

नितेश कुमार झा, सचिव।

टिप्पणी--राजपत्र, दिनांक 09—05—2020, माग 1 में प्रकाशित। [प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित——] पी0एस0यू० (आर0ई०) 03 चिकित्सा / 149—18—05—2020—150 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।